

उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी चार नई जल-विद्युत परियोजनायें

कुल 3400 किलोवाट क्षमता की स्थापना के लिए सफल बिडर्स का चयन हुआ

लखनऊ, 22 अगस्त 2012

राज्य सरकार की नवीन व अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की मंशा को साकार करते हुए आज अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न इम्पार्वर्ड समिति ने उत्तर प्रदेश में चार नई लघु जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए सफल बिडर्स के चयन का अनुमोदन कर दिया।

इम्पार्वर्ड समिति के अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता के अतिरिक्त इस बैठक में प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी-जीवेश नन्दन, उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) की निदेशक-अनामिका सिंह तथा विधि, वित्त, सिंचाई, जल-विद्युत निगम आदि विभागों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड से स्थापित की जाने वाली इन चारों लघु जल-विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 3400 किलोवाट होगी। जिसमें से 550 किलोवाट कुतुबपुर (मेरठ), 300 किलोवाट धकौली (मेरठ), 1800 किलोवाट बेतवा-1 (झांसी) तथा 750 किलोवाट अकबरपुर (बुलन्दशहर) में विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से वाणिज्यिक उत्पादन वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

550 किलोवाट कुतुबपुर (मेरठ) एवं 750 किलोवाट अकबरपुर (बुलन्दशहर) में परियोजना विकास के लिए मे. ए एम आर पावर प्रा. लि. तथा 300 किलोवाट धकौली (मेरठ), 1800 किलोवाट बेतवा-1 (झांसी) के लिए मे. ओएसिस कॉन्ट्रैक्टर एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि. को चुना गया है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता ने कहा- “राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जल-विद्युत परियोजनाओं सहित सभी प्रकार के स्रोतों की सम्भावनाओं को साकार करने का प्रयास कर रही है।”

यूपीनेडा की निदेशक, अनामिका सिंह ने बताया कि सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के नियमों के तहत अब इस निर्णय को इनर्जी टास्क फोर्स तथा मंत्री परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। जिसके बाद न्यूनतम उद्धृत मूल्य को उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ अनुमोदन तथा विकासकर्ताओं को आशय-पत्र जारी करने की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।